संख्या-16/2019/319/कनिप्र/26-3-2019-19(20)/2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक : 8 मार्च, 2019
समाज कल्याण विभाग

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 मे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2844-45/ स.क./विकास/ललितपुर/(एकीकृत)/(125)/2018-19 दिनांक 26 फरवरी,2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत जनपद ललितपुर के निम्न विवरण के अनुसार उल्लिखित विकास खण्ड एवं गांवों में कराये जाने वाले कार्यो हेतु कुल लागत रू0 981.45 लाख (रू0 नौ करोड़ इक्यासी लाख पैतालिस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा परियोजना लागत के सापेक्ष रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

जनपद- ललितपुर।				
विकास खण्ड का नाम	**ग्राम का नाम**	**कार्य का नाम**	**प्रशासकीय स्वीकृति**	**स्वीकृत की जा रही धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
ताल बेहट	**खादी**	**सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।**	**98.96**	**10.00**
जखौरा	**लागौन**	**सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।**	**99.63**	**10.00**
	मैनवारा	**सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।**	**98.87**	**10.00**
	कारी पहाड़ी	**सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।**	**99.46**	**10.00**
बिरघा	**बाला बेहट**	**सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।**	**99.13**	**10.00**
	सिमरा	**सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।**	**88.19**	**10.00**
	ककौरिया	**सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।**	**99.53**	**10.00**
	टेनगा	**सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।**	**99.60**	**10.00**
	निवउआ	**सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।**	**99.15**	**10.00**
	बछलापुर	**सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।**	**98.93**	**10.00**
		योग-	**981.45**	**100.00**

(रू0 एक करोड़ मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पूर्ण कराये जाने वाले कार्यो हेतु स्वीकृत आंगणनमें इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0(यू.पी.सी.एल.डी.एफ.)से कार्य कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 से शीघ्र एम.ओ.यू. अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को औपचारिकताएं पूर्ण कराकर उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा अति-अल्पकालीन निविदा कराकर प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष कार्यो को पूर्ण कराते हुए उपभोग प्रमाण पत्र निदेशक समाज कल्याण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-664/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(62)/ 2013 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए संबंधित जिले के संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(5) जिलाधिकारी, ललितपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणन के आधार पर कार्यदायी संस्था से कार्य कराया जायेगा जिसे लोक निर्माण विभाग के शासनादेश में प्राविधाननुसार व्यय देय होगा।

(6) प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(7) संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(8) स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं के कार्य स्वीकृत परियोजना लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराये जायेगें और भविष्य में इनका पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं की लागत मे सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र (कार्य के प्रगति/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स इत्यादि सहित)जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) ललितपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रेषित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)के लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ0संख्या-16/2019/319 (1)/क.नि.प्र./26-3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, ललितपुर ।
3- कोषाधिकारी जवाहर भवन,लखनऊ
4- वित्त नियन्त्रक, समाज कल्याण निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), ललितपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू.पी.सी.एल.डी.एफ.) लखनऊ।
7- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।